will see that the petroleum Ministry, for example, had a report of the Oil Prices Committee. That report is given in English and it is available since a long time but the Hindi translation was not available and therefore the country has been denied the advantage of having this report because the Hindi translation was not available. And, regarding the Ministry of Steel and Mines, 17 Reports were published by the Ministry last year and only 4 are available both in English and in Hindi because only 4 have Hindi translations. The rest of the 11 reports have no Hindi translations and therefore they are not laid on the Table of the House. My point is this Hindi translation must be given in good time. Until that comes, there should be no delay of laying any report in English so that the Parliament and the country would not be denied the advantage of having those reports. This is my submission and I hope that the Chair will give direction to the Government on these points so that such things are not repeated in future.

MR. DEPUTY-SPEAKER· There is a committee which will go into it. Now, Shri Pratap Chandra Chunder.

Annual Reports of National Staff College for Educational Planners and Administrators for 1970-71 to 1974-75 and for 1975-76

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR PRATAP CHANDRA CHUNDER): I beg to lay on the Table—

(1) A copy of the Report (Hindi and English versions) of the National Staff College for Educational Planners and Administrators. New Delhi, for the years 1970-71 to 1974-75

(2) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Staff College for Educational Planners and Administrators, New Delhi, for the year 1975-76.

(3) A statement (Hindi and English versions) explaining that (i) Government are in agreement with the above Reports and therefore no separate Reviews being laid and (ii) reasons for delay in laying the Reports.

[*Placed in Library. See* No. LT-1752/78].

PROF. P. G. MAVALANKAR: I have already made my submission in regard to Items 2 and 3. What is your direction, Sir?

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is a Committee which will go into the reasons for the delay.

PROF. P. G. MAVALANKAR: Now, Sir the same thing I want to say with regard to the Ministry of Education The hon. Minister of Education is my esteemd colleague but I must say that the delay is inordinate and unpardonable. These reports are prepared in 1970-71 to 1974-75 We are getting these after 8 years. If these are to come after 8 years, well, they don't have to come here We are here for 5 years only. If we cannot get them in our own term, what is the use of having these reports? There is no statement accompanying it, as to why the delay took place. The Minister has not given any reasons for the delay No reason is given

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is contained there. You please see Item No 4 sub-item (3). Please read the last line.

PROF. P. G. MAVALANKAR: For Items 2 and 3 none, Sir That is my submission.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri Ram Kinkar.

Urban Land (Ceiling & Regulation) Amendment Rules, 1978

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नगर भूमि

(उच्चतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 46 की उपधारा (3) के अन्तर्गत नगर भूमि (उच्चतम सीमा तथा विनियमन) संशोधन नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 18 फरवरी, 1978 के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 273 में प्रकाशित हुए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हू।

[*Placed in Library See* No LT-1753/78]

श्री विजय कुमार मलहोत्रा (दक्षिण दिल्ली) उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह से अंग्रेजी का वर्णन यहा आ जाता है और हिन्दी का वर्णन नही आता है तो इस तरह तो हिन्दी का वर्णन कभी आयेगा ही नही। हमे अंग्रेजी के साथ साथ ही हिन्दी का वर्णन लाने के लिये भी प्रयत्न करना चाहिए।

MR DEPUTY SPEAKER Only Mr Mavalankar has written to me earlier.

12.09 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED DEMONSTRATION IN BAREILLY AGAINST POLICE FOR SHOWING DISRESPECT TO DR AMBEDKAR.

श्री मगल देव (अकबरपुर) उपाध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह मत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे मे वक्तव्य दे —

"पुलिस द्वारा डा० बी० आर० अम्बेदकर की प्रतिमा के प्रति असम्मान प्रकट किए जाने के विरोध मे 6 मार्च, 1978 को बरेली मे अनुसूचित जातियों तथा अल्पसंख्यक समुदायो के लोगो के विशाल प्रदर्शन का समाचार।"

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार बरेली के घासी राम गौतम नामक एक व्यक्ति ने 3 फरवरी, 1978 को लकडी का एक खोखा लगाकर मुख्य सडक पर अतिक्रमण किया और उसमें एक पान की दुकान शुरु की। उसने खोखे में डा० अम्बेदकर के तीन चित्र लगाए सम्भवत: इसलिए कि प्राधिकारी खोखे को न हटाएं। और इस प्रकार बाबा साहेब अम्बेदकर का नाम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए घसीटा।

अतिक्रमण को हटाने के लिए स्थानीय प्राधिकारियो द्वारा श्री घासी राम को राजी करने के प्रयास किए गए, परन्तु सफल नही हुए। अत म्युनिसिपल बोर्ड प्राधिकारियों ने इस अतिक्रमण को सडक से हटाने के लिए पुलिस सरक्षण मे अपने कर्मचारी भेजे। दल ने अतिक्रमण को हटाने के लिए श्री घासीराम को राजी करने का पुन प्रयास किया परन्तु असफल होने पर खोखा हटाने लगे। घासी राम और उसके दो रिश्तेदारो ने इन सरकारी कर्मचारियो को अपने वैध कर्तव्यो के निर्वहन से रोका और गाली गलौज की और हाथापाई भी की। अत इन्हे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 332/353 के अन्तर्गत गिरफ्तार करना पडा और उसके बाद ही अतिक्रमण को हटाया जा सका। घासी राम ने खोखे पर लगे डा० अम्बेदकर के चित्रो को हटाने की भी परवाह नही की, अत. इन्हे अधिकारियो ने कब्जे मे ले लिया और आदर से रखा जा रहा है।उनके प्रति कोई निरादर अथवा असम्मान नही प्रगट किया गया।

कुछ तत्वो ने निजी स्वार्थवश डा० अम्बेदकर के नाम से अनुचित लाभ उठाने के प्रयास मे अनुसूचित जातियो की भावनाओ को भडकाने के उद्देश्य से, 5 मार्च, 1978 को बरेली मे एक जलूस निकाला जिसमें बताया जाता है कि लगभग 200 व्यक्तियों ने भाग लिया।